ISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 2, Issue 01, Jan-June 2019

भारतीय राजनीति में अपराधीकरण व भ्रष्टाचारः एक पुनरावलोकन

[1] **डा0 अरविन्द कुमार शुक्ल,**

[1] असिस्टेंट प्रोफेसर –राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिंदकी, फतेहपुर (उ0प्र0)

Received: 12 Jan 2019, Accepted: 15 March 2019 ; Published on line: 15 April 2019

Abstract

स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले लोग जब तक भारतीय राजनीति में रहें तब तक अपराधीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ नही हुई थी। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में चारों ओर अपराधियों की जमघट दिखाई दे रहा है। आज हमारे नेता अपराधिक चरित्र वालों को उच्च पदों पर बैठा रहे है और सज्जनों को अपमान का विष पीना पड रहा है। आज के दौर में अधिकतम राजनेता और राजनीतिक दल सत्तालोलुप है। कुर्सी पाना उनका एकमात्र लक्ष्य रह गया है, वे डाकुओं, माफिया , सरगनाओं एवं अपराधियों को पार्टी टिकट देकर चुनाव लड़वाते है। वे जानते है की जनता उनके भय और आतंक से उन्हें ही वोट देगी। वर्तमान परिदृश्य में कोई एक दल को दोषी ठहराना उचित नही होगा, सभी राजनितिक एक ही थैली के चट्टे बट्टे से है।

वर्तमान समय में संसद और विधानसभाओं में कई एसे चेहरे दिखाई देते है जिनकी वास्तविक जगह जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए थी। आज के समय में जब मिली जुली सरकार बन रही है, किसी दल के पास इतना बहुमत नही है कि वह अपने दम पर सरकार बना सके, तब वे किसी को भी अपने दल में शामिल करने को तैयार हो जाते है, चाहे वो अपराधी सांसद या विधायक ही क्यों न हो।

संकेत शब्दः भारतीय राजनीति में अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, भारतीय लोकतंत्र व कुशासन।

परिचयः

वर्तमान में भारतीय राजनीति कि स्थिति यह है कि अब अच्छे लोग इसमे आना नही चाहते है। राजनीति में भ्रष्टाचार अपनें चरम पर है। दल बदल के लिए बनाया गया कानून प्रभावी नही हो पा रहा है। आज पैसे के बल पर किसी भी दल के सांसद, विधायक को खरीदा जा सकता है। राजनीति के अपराधीकरण का परिणाम यह है कि अब संसद और विधान सभावों कि गरिमा घटी है। वहां अब लात, घूंसे, मेज, कुर्सी सब चलती है, गाली गलौज एवं मारपीट तो आम बात हो गई है। चुनाव आयोग राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए नियम तो बनाए हैं। लेकिन वह भी अबतक इसे रोकने में असमर्थ ही रही है। इस प्रकार आज लगभग सभी दल अपराधियों का उपयोग

ISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 2, Issue 01, Jan-June 2019

कर रहे हैं और जिस राजनीतिक दल को आर्थिक अपराधी का सहयोग जितना अधिक मिलता है, वह उतना अधिक ताकतवर होकर आता है। यह अवस्था हमेशा से रही है, लेकिन जब से जनता का राजनीतिकरण हुआ है, अपराधीकरण की प्रक्रिया भी तीव्र हुई ळें

आजादी के बाद सामंत मजबूत स्थिति में थे, इसलिए आम जनता उनकी बातों को ही शिरोधार्य मानकर मतदान करते थे और जब जनवादी शक्ति और सामाजिक न्याय की शक्ति के द्वारा जनता को राजनीतिक चेतना से तैयार किया गया और जब आम जनता अपने मन से अपना राजनीतिक मत (वोट) देना चाहा तो सामंती शक्ति के द्वारा या तो आम जनता को धमकाना शुरू किया गया या उनके मत त्वरित लाभ देकर या बाहुबल से जबर्दस्ती खरीदनें एवं लूटने की शुरूआत की गयी।

दुर्भाग्यवश राजनीति आज एक ऐसा विषय बन पडा है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को विशेषज्ञ मानता है, चाहे उसने इस विषय का क्रमबद्ध अध्ययन किया हो अथवा नहीं। दूसरी परिभाषा जो राजनीति की है, सुशासन करने के लिए अपनायी गयी नीति को ही राजनीति कहते हैं। तो कतिपय लोब राजनीति को दुष्ट पुरुषें का अन्तिम आश्रय स्थल भी मानते हैं, अर्थात, राजनीति सत्ता में पहुंचने का एक जरिया है, एक रास्ता है। सत्ता का अपना कोई वजूद नहीं होता है।

सत्ता एक प्रेत है, एक मुखौटा है, जो राजनीति के चेहरे पर मुखौटे के रूप पहनी जाती है, राजनीति सत्ता की बात बोलने लगती है। सत्ता का धर्म है निरंकुश होना, यानि सत्ता निरंकुश हुए बिना शासन कर ही नहीं सकती है, इसलिए निरंकुशता ही अपराध है। कहने का मतलब यह है कि राजनीति जब से लोगों के दिमाग में आई, तब से अपराध उसका अभिन्न अंग बन गया। सत्ता और संपत्ति के बीच के बीच हुआ समझौता भ्रष्टाचार कहलाता है।

कोई कंपनी किसी नौकरशाह को इसलिए घूस देता है क्योंकि नौकरशाह के पास सत्ता (शक्ति, पावर) है, नहीं तो कोई कंपनी किसी को क्यों संपत्ति हस्तांतरण करेगा और यदि किसी के पास संपत्ति ही नहीं हो तो घूस का प्रश्न भी नहीं उठता है। इसमें दोंनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाता है। घूस के कारण नौकरशाह अनैतिक कार्य (अधिकार से बाहर) भी करता है जैसे किसी सार्वजनिक क्षेत्र को जब निजीकरण किया जाता है उसमें दोंनों आपस में 50–50 का अंशदान प्राप्त करता है। सौ करोड़ की संपत्ति जब किसी कंपनी को बेची जाती है तो उसका मूल्य का मात्र 20 लाख मूल्यांकन किया जाता है और शेष दोंनों के बीच बंटवारा हो जाता है, इसी प्रकार हर सौदे में यही प्रक्रिया चलती है।

भारत में सब्सिडी अभी तक इसलिए चालू है, क्योंकि कंपनी और नौकरशाह के बीच भ्रष्टाचार का रिश्ता है। जैसे जनवितरण प्रणाली में ही 40 प्रतिशत फर्जी कार्ड है और इस फर्जी कार्ड को दिखाकर सब्सिडी के बढे हुए हिस्से का बंटवारा होता है।

कुछ समय पूर्व सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि जब मतदाताओं को किसी व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड मालूम होगा तो वह उसे किसी हालत में वोट नहीं देगा। परंतु जब व्यवहार में इसे देखा गया तो आपराधिक छवि के अधिक से अधिक लोग जीत कर आ गए और इस तरह के हलफनामे का

ISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 2, Issue 01, Jan-June 2019

कोई असर नहीं पडा। मीडिया द्वारा बार–बार आग्रह किया जाता है कि विभिन्न पार्टियां आपराधिक छवि के लोगों को टिकट नहीं दें, परंतु व्यवहार में कोई भी पार्टी इसका पालन नही करती है। ट्रांसपेरंसी इन्टरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में संसार के 174 देशों में भ्रष्टाचार और राजनीतिक अपराधीकरण के मामले में भारत को स्थान 72वां प्रदान किया है।

स्वतंत्रता के बाद पिछले 60 वर्ष में अपने देश में लोकतंत्र मजबूत तो हुआ है, लेकिन राजनीति का अपराधीकरण भी बढा है, जिससे चुनावों के साफ–सुथरे होने पर संदेह के बादल गहराने लगे हैं। दिनों–दिन यह मुद्दा लोकतंत्र के भविष्य के लिहाज से अहम होता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपराधिक तत्वों की सहायता लेना तो अब बहुत छोटी बात हो गई है, अब तो बाकायदा उनकों टिकट देकर उपकृत किया जा रहा है। भारत का कोई भी राजनैतिक दल ऐसा नहीं है जिसमें किसी न किसी प्रकार के अपराधी न हो।

लोकसभा और राय विधानसभाओं में यदि अपराधियों का रिकॉर्ड देखा जाए तो यह देखकर घोर आश्चर्य होता है कि अपराधियों की संख्या दिनोंदिन बढती ही जा रही है। कुछ वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि यदि कोई व्यक्ति संसद या विधानसभा के चुनाव का प्रत्याशी है तो वह यह हलफनामा देगा कि उसके खिलाफ कितने आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट का यह अनुमान था कि जब वोटरों को किसी व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड मालूम होगा तो वह उसे किसी हालत में वोट नहीं देगा। परंतु जब व्यवहार में इसे देखा गया तो अपराधिक छवि के अधिक से अधिक लोग जीत कर आ गए और इस तरह के हलफनामे का कोई असर नहीं पडा। मीडिया द्वारा बार–बार आग्रह किया जाता है कि विभिन्न पार्टियां आपराधिक छवि के लोगों को टिकट नहीं दें, परंतु व्यवहार में कोई भी पार्टी इसका पालन नही करती है।

ट्रांसपैरेंसी इन्टरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि संसार के 174 देशों में भ्रष्टाचार और राजनीतिक अपराधीकरण के मामले में भारत का स्थान 72वां है। यहां तक कि संसद में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लगभग एक तिहाई सांसद हैं, जिन पर कुल 413 मामले लंबित हैं।

लोकसभा और विधानसभाओं में अपराधियों की संख्या तब और ज्यादा बढ गई जब एक पार्टी के बदले कई पार्टियों की मिलीजुली सरकार बनने लगी, खासकर क्षेत्रीय पार्टियों में इतने अपराधी भरे पडे हैं कि उनकी कोई गणना भी नहीं कर सकता है। तर्क दिया जाता है कि जब तक किसी व्यक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपराध साबित नहीं हो जाता है।

तब तक उसे अपराधी कैसे कह सकते हैं। पिछले अनेक वर्षों से तमाम संगठन अपराधियों के निर्वाचित होने के अधिकार पर सवाल खडा कर रहे हैं। फिर भी विधानसभाओं तथा संसद में अपराधियों की संख्या कम होने के स्थान पर बढती ही जा रही है। कोई भी यह नहीं बताता है कि जनता आखिर अपराधियों को क्यों चुन कर भेजती है। यह तो तय है कि उनके गले पर अपराधियों की बन्दूकें नहीं लगी होतीं और तो और अब तो बात यहाँ तक आ चुकी है कि जो जितना बडा अपराधी होगा उसके जीतने की उम्मीद भी अधिक होगी ।

जब तक इस सवाल का जवाब नहीं तलाशा जाएगा कि आम जनता ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले नेताओं को छोडकर अपराधियों को ही वोट क्यों देती है, तब तक अपराधियों को निर्वाचित होने से नहीं रोका जा सकता है। यह तय है कि अपराधियों को निर्वाचित होने से रोकने के लिये बनाए जाने वाले कानून एक दिन स्वयं लोकतंत्र का ही गला घोंट देंगे। एक और चौंकाने वाली बात है कि स्विस सरकार के नवीन घोषणा के अनुसार यदि भारत सरकार उनसे मांगे तो वह यह बता सकते हैं कि उनके बैंकों में किन भारतीयों के कितने पैसे जमा है। अब तो यह सभी को पता चल चुका है, उन बैकों में सर्वाधिक पैसा भारतीय नेताओं व काले बाजारियों का ही जमा है।

अतः अगर राजा एवं प्रजा दोनों सचेत हो जाएँ तथा सच्चे सदाचार को अपना लें, तो भ्रष्टाचार का नामो निशान मिट जायेगा। जनता एवं सरकार दोनों को ही जागृत होना ही पड़ेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- Corruption in India By K. N. Gupta –foreword in N. vital ..Anmol publications PVT. LTD. New delhi p-27-56
- Corruption in Indian politics and bureaucracy-Satyavan Bhatnagar, S. K. Sharma, Panjab University. Directorate of Correspondence Courses - 1991 - 199 pages - Snippet view Ess Ess Publications, 1991Original from ISBN 8170001234, 9788170001232 p-43-87
- Title Indian bureaucracy at the crossroads ,Author Syamal Kumar Ray ,Publisher Sterling, 1979 ,Original from the University of California Digitized 10 Jan 2008 P-52-98
- Title Corruption in Indian politics and bureaucracy ,Volume 5 of Panjab University D.C.C. publications ,Authors Satyavan Bhatnagar, Panjab University. Directorate of Correspondence Courses ,Editor S. K. Sharma, Publisher Ess Ess Publications, 1991,Original from the University of California,Digitized 22 Jan 2007, ISBN 8170001234, 9788170001232 P53-69
- Title The history of corruption in central government ..Issue 7 of Cahier d'histoire de l'administration.. Volume 21 of International Institute of Administrative Sciences monographs.. Author, Editor & Contributor- Seppo Tiihonen .Edition illustrated ,Publisher IOS Press, 2003 - ISBN 1586033166, 9781586033163
- http://www.facebook.com/notes/
- http://www.hindimedia.in/content/view/690/43/index.php?option=com_content&task=view&id=15185&Itemid=86
- http://bhadas4india.com/index.php?option=com_content&view=article&id=223:2011-06-12-17-53-41&catid=34:headline
- http://forum.jagranjunction.com/2011/04/16/to-save-democracy-aamran-anshan-is-blackmailing/
- राजनीति का अपराधीकरण या अपराध का राजनीतिकरण
  http://www-deshbandhu-co-in/newsdetail/4185/9/199

- Corruption in India By K. N. Gupta –foreword in N. vital ..Anmol publications PVT. LTD. New delhi p-27-56
- ***Corruption*** in ***Indian*** politics and bureaucracy-Satyavan Bhatnagar, S. K. Sharma, Panjab University. Directorate of Correspondence Courses - 1991 - 199 pages - Snippet view Ess Ess Publications, 1991 Original from ISBN 8170001234, 9788170001232 p-43-87
- राजनीति की कठपुतली बन गये हैं नेता http://dr-mahesh-parimal.blogspot.in/2010/01/blog-post_07.html
- http://www.hindimedia.in/content/view/690/43/index.php?option=com_content&task=view&id=15185&Itemid=86
- http://bhadas4india.com/index.php?option=com_content&view=article&id=223:2011-06-12-17-53-41&catid=34:headline
- शर्मा शशि, राजनीतिक समाजशस्त्र की रुपरेखा, *PHI Learning Pvt. Ltd.*delhi, ISBN-8120339827, 9788120339828
- राजनीति का अपराधीकरण http://hullchal.blogspot.in/2009/02/blog-post.html
- http://dr-mahesh-parimal.blogspot.in/2010/01/blog-post_07.html
- http://forum.jagranjunction.com/2011/04/16/to-save-democracy-aamran-anshan-is-blackmailing/
- **दैनिक जागरण,** 20 –06–2018, कानपुर संस्करण
- **अमर उजाला,** 08–06–2017, कानपुर संस्करण
- **द हिन्दू ,** 06–06–2018, दिल्ली संस्करण
- **दैनिक आज,** 12 –06–2018, कानपुर संस्करण
- **दैनिक आज,** 23 –03–2018, कानपुर संस्करण
- Think Tank